International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 15 Issue 10 || October 2026 || PP. 79-86

21वीं सदी में भारत–नेपाल संबंध: साझा विकास की संभावनाएँ एवं भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

अनिल कुमार [1] एवं डॉ. अमित कुमार [2]

1. अनिल कुमार -शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,बी.आर.अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

2. डॉ. अमित कुमार- सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, मुंशी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी, (बी.आर.अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर) बिहार

सार

21वीं सदी में भारत–नेपाल संबंध ऐतिहासिक निकटता और सांस्कृतिक साझेदारी के साथ आगे बढ़कर बहुआयामी सहयोग के स्वरूप में विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक समानता, खुली सीमा व्यवस्था तथा परस्पर निर्भरता/पारस्परिकता ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थायित्व प्रदान किया है। यह पारस्परिकता वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा सहयोग, जलविद्युत विकास, आधारभूत संरचना निर्माण एवं विकास, व्यापार, पर्यटन तथा शैक्षिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में हुए उल्लेखनीय विकास में देखे जा सकते हैं। आपसी संबंधों में आई गर्माहट ने ना केवल दोनों देशों के बीच के संबंधों की प्रगाढ़ता को रेखांकित किया है अपितु क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान की है।

बहरहाल, दोनों देशों के बीच के संबंधों में सब अच्छा हीं नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों ने भारत-नेपाल संबंधों के समक्ष नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता सीमा क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न हाल के दिनों में दोनों देशों के समाचार में सुर्खियों में रहे हैं. और दोनों के बीच आपसी संबंधों में तनाव का कारण भी रहे हैं। समय-समय पर राजनीतिक एवं कूटनीतिक तनाव का कारण बने हैं. दूसरी तरफ नेपाल की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता एवं राष्ट्रवादी विमर्शों ने दोनों देशों के आपसी मंशाओं के प्रति आशंकाओं को कई गुणा बढ़ा दिया है. दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में चीन की बढ़ती सक्रियता और नेपाल की इसमें भूमिका को लेकर भारत की भू-राजनीतिक, रणनीतिक एवं सामरिक चिंताओं में भी काफी बढ़ोतरी की है। यह पत्र इस बात की भी समीक्षा करेगा की नेपाल की बदलती नीतियों में भारत अपनी विदेश नीति व सीमापार की नीतियों में किस प्रकार बदलाव ला रहा है? दोनों देशों के मध्य रिश्तों में आ रहे उतार-चढ़ावों को नियंत्रित, बेहतर और शसक्त बनाने के उपायों और सुझावों पर चर्चा शोधपत्र के अंत में है. यह शोध पत्र दोनों देशों के बीच की इन्ही बारीक ताने-बाने को समझने का प्रयास करता है साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी शंकाओं को दूर कर एक साझा और समृद्ध भविष्य के लिए नयी राहों को तलाशने का भी प्रयास करता है।

मुख्य शब्द: भारत–नेपाल संबंध, 21वीं सदी, सीमा विवाद, भू-राजनीति, चीन की भूमिका, कूटनीति, आर्थिक सहयोग, जल संसाधन, सुरक्षा, क्षेत्रीय साझेदारी

21वीं सदी में भारत–नेपाल संबंध: साझा विकास की संभावनाएँ एवं भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

परिचय

भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन संबंधों की आधारशिला ऐतिहासिक निकटता, सांस्कृतिक समानता, धार्मिक परंपराओं, खुली सीमा व्यवस्था तथा गहरे सामाजिक-

आर्थिक अंतर्संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सदियों से विद्यमान जनस्तरीय संपर्कों ने पारस्परिक सहयोग और विश्वास को निरंतर सुदृढ़ किया है। वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि ने इन संबंधों को संस्थागत आधार प्रदान किया, किंतु बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों की भिन्न प्राथमिकताओं ने समय-समय पर द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताएँ उत्पन्न की हैं (Muni, 2003; Nayak, 2010)। इक्कीसवीं सदी में नेपाल के लोकतांत्रिक संक्रमण, संवैधानिक पुनर्गठन तथा विदेश नीति में बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता ने भारत–नेपाल संबंधों को नए आयाम प्रदान किए हैं। विशेष रूप से कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा और सुस्ता सीमा विवाद, जल संसाधनों के उपयोग, व्यापारिक असंतुलन तथा संप्रभुता संबंधी संवेदनशीलताओं ने द्विपक्षीय विश्वास को प्रभावित किया है (Aryal & Pulami, 2024)। इसके अतिरिक्त, नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं रणनीतिक सक्रियता तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने हिमालयी क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अधिक जटिल बनाया है (Murton & Lord, 2020)।

तथापि, इन चुनौतियों के समानांतर जलविद्युत, ऊर्जा व्यापार, परिवहन संपर्क, आधारभूत संरचना, पर्यटन, शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोधपत्र भारत–नेपाल संबंधों की ऐतिहासिक एवं संस्थागत पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए समकालीन राजनीतिक, आर्थिक और भू-रणनीतिक चुनौतियों की समीक्षा करता है। साथ ही, यह नेपाल की संतुलनकारी विदेश नीति, भारत की बदलती पड़ोस नीति तथा क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के प्रभावों का परीक्षण करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, विश्वास और साझा विकास पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं का मूल्यांकन करना है।

ऐतिहासिक एवं संस्थागत पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक निकटता पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों की अभिव्यक्ति राम–सीता विवाह से जुड़ी मिथिला–अयोध्या परंपरा तथा लुम्बिनी और बोधगया की साझा बौद्ध विरासत में दिखाई देती है। इसी प्रकार मैथिली, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाओं, धार्मिक उत्सवों, पारिवारिक संबंधों तथा सामाजिक परंपराओं की समानता ने इन संबंधों को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच प्रचलित 'रोटी-बेटी का संबंध' इसी सांस्कृतिक एवं सामाजिक आत्मीयता का प्रतीक है (सिंह, 2018; वर्मा, 2023; Nair & Meena, 2025)।

आधुनिक भारत–नेपाल संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अठारहवीं शताब्दी में पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखा राज्य के विस्तार से जुड़ी है। गोरखा शासकों की विस्तारवादी नीति और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप आंग्ल–नेपाल युद्ध (1814–1816) हुआ। इसके उपरांत संपन्न सुगौली संधि (1816) के अंतर्गत नेपाल को कुमाऊँ, गढ़वाल और तराई के कुछ क्षेत्रों से अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। इस संधि ने नेपाल की क्षेत्रीय सीमाओं को पुनर्परिभाषित किया तथा ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, यद्यपि नेपाल ने अपनी संप्रभुता बनाए रखी। वर्तमान भारत–नेपाल सीमा विवादों की ऐतिहासिक जड़ें भी इसी संधि और इसकी भौगोलिक व्याख्याओं में निहित हैं (Pemble, 1971; Stiller, 1973; Whelpton, 2005)। औपनिवेशिक काल में नेपाल और ब्रिटिश भारत के संबंध मुख्यतः सामरिक एवं राजनीतिक सहयोग पर आधारित रहे। वर्ष 1857 के विद्रोह में जंग बहादुर राणा ने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, जिसके बाद 1860 में पश्चिमी तराई के कुछ क्षेत्र नेपाल को वापस किए गए। ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती तथा दोनों विश्व युद्धों में नेपाल के सहयोग ने इन संबंधों को सुदृढ़ किया। वर्ष 1923 की ब्रिटेन–नेपाल संधि ने नेपाल की स्वतंत्र स्थिति को औपचारिक मान्यता प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोरखा रेजिमेंटों का भारत और ब्रिटेन के बीच विभाजन हुआ (Rose, 1971; Stiller, 1973)। स्वतंत्र भारत और नेपाल के संबंधों में 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षरित शांति और मैत्री संधि एक निर्णायक पड़ाव सिद्ध हुई। इस संधि ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, नागरिकों की आवाजाही, निवास, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए संस्थागत आधार प्रदान किया। प्रारंभिक वर्षों

में भारत ने नेपाल के लोकतांत्रिक विकास, प्रशासनिक आधुनिकीकरण और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग किया (Bhasin, 1970)। तथापि, वर्ष 1960 में राजा महेंद्र द्वारा निर्वाचित बी. पी. कोइराला सरकार को बर्खास्त किए जाने तथा पंचायती व्यवस्था की स्थापना से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। इसी दौरान नेपाल ने चीन के साथ संबंधों का विस्तार करते हुए अपनी विदेश नीति में अधिक स्वायत्तता और शक्ति-संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। वर्ष 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान नेपाल की तटस्थता ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाया। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक सहयोग जारी रहा। नेपाल की संतुलनकारी विदेश नीति की अभिव्यक्ति राजा बीरेंद्र द्वारा 1975 में प्रस्तुत 'शांति क्षेत्र' (Zone of Peace) के प्रस्ताव में भी दिखाई देती है। दूसरी ओर, 1989 में व्यापार एवं पारगमन संबंधी विवाद और आपूर्ति अवरोधों ने द्विपक्षीय अविश्वास को गहरा किया। इसके बाद 1990 के जनआंदोलन से संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, जबकि 1996 में प्रारंभ माओवादी विद्रोह ने नेपाल की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न कीं (Muni, 2003; Jha, 1995)।

भारत-नेपाल संबंधों के बीच प्रमुख मुद्दे

इक्कीसवीं सदी में नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन ने भारत–नेपाल संबंधों को नए आयाम प्रदान किए। वर्ष 2005 का बारह-सूत्रीय समझौता, 2006 का लोकतांत्रिक जनआंदोलन तथा व्यापक शांति समझौता नेपाल के लोकतांत्रिक संक्रमण में निर्णायक सिद्ध हुए। अंततः 28 मई 2008 को नेपाल ने लगभग 240 वर्ष पुरानी राजशाही समाप्त कर स्वयं को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इन परिवर्तनों में भारत की कूटनीतिक भूमिका महत्त्वपूर्ण रही, किंतु नेपाल की बदलती घरेलू राजनीति और चीन की बढ़ती सक्रियता ने द्विपक्षीय संबंधों में नई भू-रणनीतिक जटिलताएँ उत्पन्न कीं (Adhikari, 2014; Jha, 2014; Muni, 2016)। नेपाल में 20 सितंबर 2015 को लागू नए संविधान ने संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। हालाँकि, प्रांतीय सीमांकन, नागरिकता संबंधी प्रावधानों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मधेशी समुदायों ने गंभीर आपत्तियाँ व्यक्त कीं। इसके परिणामस्वरूप तराई क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन और सीमा-पार आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुए। नेपाल के कुछ राजनीतिक वर्गों ने भारत पर अघोषित आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया, जबकि भारत ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए आंतरिक विरोध प्रदर्शनों को आपूर्ति संकट का प्रमुख कारण बताया। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक अविश्वास को बढ़ाया (Ministry of External Affairs, 2016)। इसके अतिरिक्त, कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद ने द्विपक्षीय संबंधों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े प्रश्नों को पुनः प्रमुखता प्रदान की।

I. कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा और सुस्ता सीमा विवाद

19 मई 2020 को प्रतिनिधि सभा में अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने घोषणा की कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के हैं और सरकार राजनयिक प्रयासों के जरिए इन्हें वापस हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान की अनुसूची 3, जिसमें नेपाल का नक्शा शामिल है, उसमें संशोधन करके इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा (Kamat, 2020)। अगले दिन, भूमि प्रबंधन मंत्री पद्मा कुमारी आर्याल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसे कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दी थी। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने आधिकारिक मानचित्र में सम्मिलित किया. इस नक्शे के जुड़ने से नेपाल के क्षेत्र में 335 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया (Post Report, The Kathmandu Post, 2020)। हालाँकि, यह विवाद इन घटनाओं से पहले ही मौजूद था। नेपाल का यह नक्शा, नवंबर 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत द्वारा जारी संशोधित राजनीतिक मानचित्र तथा मई 2020 में धारचूला–लिपुलेख सड़क के उद्घाटन से शुरू होता है, जिसने इस विवाद को पुनः द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में ला दिया और क्षेत्रीय संप्रभुता के प्रश्न को दोनों देशों ने राष्ट्रीय अस्मिता और घरेलू राजनीतिक वैधता से जोड़ दिया (ibid.; Aryal & Pulami, 2024; Sharma, 2025 A)। और इस तरह भारत–नेपाल संबंधों में तनाव का

एक प्रमुख कारण क्षेत्रीय विवाद जुड़ गया । इन विवादों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्ष 1816 की सुगौली संधि में निहित है, जो आंग्ल–नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। संधि के अनुच्छेद V में काली नदी को सीमा निर्धारण का महत्त्वपूर्ण आधार बनाया गया था। हालांकि, काली नदी के वास्तविक उद्गम, ऐतिहासिक मानचित्रों तथा औपनिवेशिक काल के सीमा अभिलेखों की अलग-अलग व्याख्याओं ने कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावों को जन्म दिया। नेपाल लिम्पियाधुरा को काली नदी का उद्गम मानता है, जबकि भारत ऐतिहासिक अभिलेखों और प्रशासनिक नियंत्रण की अपनी व्याख्या के आधार पर इस क्षेत्र पर दावा करता है (International Crisis Group, 2005; Kumar, 2021; Verma, 2022)।

दूसरी ओर, सुस्ता क्षेत्र में गंडक नदी के प्रवाह में ऐतिहासिक परिवर्तन तथा सीमा निर्धारण की जटिलताओं ने अलग प्रकार का क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न किया है (Verma, 2022)। इस प्रकार, सीमा विवाद केवल भौगोलिक सीमांकन का प्रश्न नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रवाद, ऐतिहासिक स्मृति और द्विपक्षीय विश्वास से संबंधित संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं।

II. वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि तथा संप्रभुता संबंधी प्रश्न

वर्ष 1950 की भारत–नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के विशेष संबंधों का आधार रही है, किंतु नेपाल में इसके कुछ प्रावधानों को असमान और भारत-केंद्रित मानने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही है। विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी परामर्श, आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक सुविधाओं तथा विदेशी नीति की स्वतंत्रता को लेकर संधि की व्याख्या पर मतभेद रहे हैं। नेपाल के कुछ राजनीतिक समूह इसे ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति-संबंधों का प्रतीक मानते हैं, जबकि भारत इसे दोनों देशों के बीच विशेषाधिकारों और पारस्परिक सहयोग की संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखता है (Muni, 2015; Nayak, 2010)। संधि की पुनर्समीक्षा पर सहमति के बावजूद ठोस परिवर्तन का अभाव समय-समय पर द्विपक्षीय असंतोष को बढ़ाता रहा है।

III. जल संसाधनों का बँटवारा और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े मतभे

भारत–नेपाल संबंधों में साझा जल संसाधनों का उपयोग और लाभों का न्यायसंगत वितरण एक अन्य महत्त्वपूर्ण विवादास्पद विषय रहा है। कोसी समझौता (1954), गंडक समझौता (1959) और महाकाली संधि (1996) के अंतर्गत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत उत्पादन तथा परियोजनाओं से प्राप्त लाभों के वितरण को लेकर समय-समय पर असहमति सामने आई है। नेपाल में यह धारणा रही है कि कुछ परियोजनाओं से अपेक्षित लाभों का समान वितरण नहीं हुआ, जबकि भारतीय दृष्टिकोण में इन समझौतों को दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी माना गया है (Jha, 2013)। विशेष रूप से पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, जल उपयोग के अधिकारों की अलग-अलग व्याख्या तथा परियोजना के लाभ और लागत के निर्धारण से जुड़े प्रश्न द्विपक्षीय जल सहयोग की प्रमुख बाधाएँ हैं। वसानी (Vasani, 2023) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय जल कानून में समान अधिकार, न्यायसंगत उपयोग और लाभ-साझेदारी संबंधी अस्पष्टताएँ भारत और नेपाल के बीच जल संसाधनों पर समझौता स्थापित करने को कठिन बनाती हैं। इस प्रकार, जल संसाधनों के प्रश्न में तकनीकी और आर्थिक हितों के साथ संप्रभुता तथा राजनीतिक विश्वास के मुद्दे भी अंतर्निहित हैं।

IV. नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत–चीन भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक, राजनीतिक और अवसंरचनात्मक उपस्थिति ने भारत–नेपाल संबंधों को व्यापक क्षेत्रीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जोड़ दिया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), हिमालयी संपर्क परियोजनाओं तथा नेपाल के साथ बढ़ते कूटनीतिक संबंधों ने भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं को प्रभावित किया है। भारत नेपाल को अपनी उत्तरी सुरक्षा व्यवस्था और हिमालयी भू-रणनीतिक परिवेश का महत्त्वपूर्ण घटक मानता है। इसके विपरीत, नेपाल अपनी विदेश नीति में स्वायत्तता बनाए रखते हुए दोनों पड़ोसी शक्तियों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार करना

चाहता है (Muni, 2015; Murton & Lord, 2020)। इस संदर्भ में नेपाल को केवल भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा का निष्क्रिय क्षेत्र मानना उचित नहीं होगा। नेपाल की आंतरिक राजनीति, विकासात्मक आवश्यकताएँ तथा विदेश नीति में विविधीकरण की आकांक्षा भी इस त्रिकोणीय संबंध को प्रभावित करती हैं। तथापि, भारत और चीन के बीच रणनीतिक अविश्वास बढ़ने की स्थिति में नेपाल की संतुलनकारी नीति द्विपक्षीय संबंधों में अतिरिक्त संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकती है।

V. आर्थिक निर्भरता, व्यापार असंतुलन और संपर्क संबंधी चुनौतियाँ

नेपाल की अर्थव्यवस्था का भारत के साथ गहरा संबंध होने के बावजूद व्यापार असंतुलन, पारगमन सुविधाओं पर निर्भरता, सीमा-पार व्यापार में प्रशासनिक बाधाएँ तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब समय-समय पर असंतोष का कारण बने हैं। समुद्र तक प्रत्यक्ष पहुँच न होने के कारण नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय पारगमन मार्गों और बंदरगाहों पर काफी निर्भर है। इस संरचनात्मक निर्भरता को नेपाल के कुछ राजनीतिक वर्ग आर्थिक असुरक्षा और विदेश नीति की सीमित स्वायत्तता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी ओर, भारत के लिए नेपाल के साथ आर्थिक एकीकरण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, ऊर्जा व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए आर्थिक परस्पर निर्भरता दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार होने के साथ-साथ राजनीतिक तनाव की स्थिति में संवेदनशीलता का स्रोत भी बन सकती है (Muni, 2015)।

भारत–नेपाल संबंधों में उत्पन्न तनाव को केवल सीमा विवाद अथवा किसी एक राजनीतिक घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके पीछे ऐतिहासिक संधियों की अलग-अलग व्याख्याएँ, संप्रभुता संबंधी संवेदनशीलताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप की धारणाएँ, जल संसाधनों के उपयोग में मतभेद, आर्थिक असमानताएँ तथा भारत–चीन भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे परस्पर जुड़े कारक कार्यरत हैं। आर्याल और पुलामी (Aryal & Pulami, 2024) तथा शर्मा (Sharma, 2025 B) के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्रीय विवादों का राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श में रूपांतरण इनके समाधान को और जटिल बना सकता है। इसलिए ऐतिहासिक मानचित्रों और संधियों की संयुक्त समीक्षा, सीमा-समितियों की नियमित बैठकें, जल संसाधनों में पारदर्शी लाभ-साझेदारी तथा नेपाल की संप्रभुता के प्रति संवेदनशील कूटनीतिक दृष्टिकोण द्विपक्षीय विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हैं। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दोनों देशों को असमान शक्ति-संबंधों की धारणाओं से आगे बढ़कर पारस्परिक सम्मान, राजनीतिक स्वायत्तता और साझा आर्थिक हितों पर आधारित सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी।

भारत–नेपाल सम्बंध: साझा विकास की संभावनाएँ

इन राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग निरंतर विस्तृत हुआ है। सितंबर 2019 में प्रारंभ मोतिहारी–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन ऊर्जा सहयोग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही। मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार तेल पाइपलाइन है। यह भारत के बिहार राज्य के पूर्वी चंपरा जिले से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई यह पाइपलाइन ईंधन के परिवहन खर्च को काफी कम करती है, टैंकर-ट्रकों की भीड़ को घटाती है और नेपाल की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाती है (SAARC Energy Centre, २०२०)। इसी प्रकार नेपाल की सीमा पार करने वाली अरुण नदी पर स्थित अरुण-3 (900 MW) और अरुण-4 (495 MW) जलविद्युत परियोजनाएं, भारत के साथ सीमा-पार बिजली एकीकरण के लिए मुख्य निवेश का काम करती हैं (Pandey, 2020)। इसके साथ ही, 1996 की महाकाली संधि के अंतर्गत आने वाली द्विपक्षीय पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य हिमालयी बेसिन में ऊर्जा ग्रिड का विस्तार करना, सिंचाई की सुविधा देना और नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के असर को कम करना है (Pun, 2011)। परिवहन एवं व्यापारिक संपर्क के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सीमा पार कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे के

आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक प्रयास जारी हैं। जयनगर-कुर्था रेल सेवा ने दोनों देशों के बीच ब्रॉडगेज यात्री सेवाओं को फिर से शुरू कर क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ावा दिया है। वहीं प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेल परियोजना से हिमालयी क्षेत्र में सीधी और तीव्र माल ढुलाई एवं जान-संपर्क स्थापित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, बीरगंज, विराटनगर और नेपालगंज में एकीकृत जाँच चौकियाँ (ICPs) स्थापित की गई हैं, जिससे व्यापार सुविधा में सुधार हुआ है, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है और लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय में कमी आई है (Chand, 2020; Ministry of External Affairs, 2024; Shrestha & Tamrakar, 2025)। सांस्कृतिक एवं मानवीय सहयोग में भी दोनो देशों के बीच उल्लेखनिए द्विपक्षीय मज़बूती देखने को मिलती है। वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा संचालित 'ऑपरेशन मैत्री', कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2021 में नेपाल को आवास्यक राहतसामग्री की आपूर्ति तथा लुम्बिनी में प्रस्तावित बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र जैसी पहलें इस सहयोग को रेखांकित करती हैं (Ministry of External Affairs, 2016, 2023)। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान, तकनीकी सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कौशल विकास में साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों को अधिक जनोन्मुखी बना सकती है। इसी प्रकार, अयोध्या–जनकपुर और लुम्बिनी–बोधगया जैसे सांस्कृतिक संपर्क भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साझा नदी प्रणालियों, बाढ़ प्रबंधन, हिमालयी पारिस्थितिकी और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सहयोग भी आवश्यक है।

नेपाल की अपार जलविद्युत क्षमता और भारत का विशाल ऊर्जा बाजार परस्पर पूरक हैं। अरुण-3, लोअर अरुण तथा पंचेश्वर जैसी परियोजनाएँ ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। हालाँकि, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी वित्तपोषण, पर्यावरणीय संरक्षण और न्यायसंगत लाभ-वितरण आवश्यक हैं (Upreti, 2010; Vasani, 2023)। इसी प्रकार, रेल, सड़क, पेट्रोलियम पाइपलाइन और एकीकृत जाँच चौकियों का विस्तार व्यापारिक लागत घटाकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत कर सकता है (Ministry of External Affairs, 2024)। इसके बावजूद बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने की आवश्यकता उत्पन्न की है। विशेष रूप से नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक, कूटनीतिक और अवसंरचनात्मक सक्रियता के संदर्भ में भारत को पारंपरिक प्रभाव-केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक विश्वास और साझा विकास पर आधारित नीति अपनाने की आवश्यकता है। मुनि (Muni, 2015) के अनुसार, नेपाल की राजनीतिक संवेदनशीलताओं और संप्रभुता का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

चीन कारक के संदर्भ में जॉनी (Johny, 2024) नेपाल की विदेश नीति को हेजिंग रणनीति के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जिसके माध्यम से नेपाल दोनों पड़ोसियों के साथ संबंध विकसित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। मर्टन और लॉर्ड (Murton & Lord, 2020) भी हिमालयी संपर्क परियोजनाओं के आर्थिक और भू-राजनीतिक आयामों को रेखांकित करते हैं। अतः भारत के लिए अधिक प्रभावी विकल्प नेपाल पर रणनीतिक दबाव बनाने के बजाय विश्वसनीय निवेश, समयबद्ध परियोजनाओं, व्यापारिक सुविधाओं तथा राजनीतिक संवाद के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता बढ़ाना होगा। इस प्रकार, संप्रभुता के सम्मान, आर्थिक पूरकता और संस्थागत विश्वास पर आधारित साझेदारी न केवल चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति सुदृढ़ करेगी, बल्कि व्यापक दक्षिण एशियाई स्थिरता और समृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगी।

निष्कर्ष

इक्कीसवीं सदी में भारत–नेपाल संबंध ऐतिहासिक निकटता, सांस्कृतिक समानता, भौगोलिक अंतर्संबद्धता और गहरी सामाजिक-आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित एक विशिष्ट बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संबंधों में जलविद्युत, ऊर्जा व्यापार, परिवहन एवं सीमा-पार अवसंरचना, पर्यटन, शिक्षा, डिजिटल संपर्क और

आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझा विकास की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं। विशेष रूप से नेपाल की समृद्ध जलविद्युत क्षमता और भारत का विशाल ऊर्जा बाजार दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी आर्थिक सहयोग का आधार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, बेहतर परिवहन एवं पारगमन सुविधाएँ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को गति दे सकती हैं, जबकि धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध, खुली सीमा और जनस्तरीय संपर्क द्विपक्षीय संबंधों की सामाजिक आधारशिला को सुदृढ़ करते हैं।

तथापि, इन संभावनाओं के बावजूद सीमा विवाद, राजनीतिक अस्थिरता, संप्रभुता संबंधी संवेदनशीलताएँ, व्यापारिक असंतुलन तथा घरेलू राजनीतिक हितों के लिए द्विपक्षीय मुद्दों का उपयोग पारस्परिक विश्वास को प्रभावित करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक, अवसंरचनात्मक और कूटनीतिक सक्रियता ने हिमालयी क्षेत्र के भू-राजनीतिक समीकरणों को अधिक जटिल बनाया है। यद्यपि चीनी निवेश नेपाल के लिए विकास और संपर्क के नए अवसर प्रस्तुत करता है, तथापि कुछ परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, ऋण संबंधी दायित्वों और संभावित रणनीतिक प्रभावों को लेकर चिंताएँ भी विद्यमान हैं। दूसरी ओर, भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति, विकासात्मक सहयोग और भौगोलिक-सांस्कृतिक निकटता द्विपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ करने के महत्त्वपूर्ण आधार बने हुए हैं।

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत–नेपाल संबंधों का भविष्य केवल ऐतिहासिक आत्मीयता अथवा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता की स्वीकृति, रणनीतिक संवेदनशीलता, संस्थागत संवाद और न्यायसंगत विकास सहयोग पर निर्भर करेगा। विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भारत के लिए अधिक प्रभावी विकल्प नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हुए आर्थिक रूप से विश्वसनीय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख साझेदारी विकसित करना होगा। वहीं, नेपाल के लिए दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतः यदि दोनों देश अल्पकालिक राजनीतिक हितों और पारस्परिक अविश्वास के स्थान पर दीर्घकालिक सहयोग, समानता और साझा समृद्धि को प्राथमिकता दें, तो भारत–नेपाल संबंध न केवल द्विपक्षीय विकास, बल्कि व्यापक दक्षिण एशियाई स्थिरता, क्षेत्रीय एकीकरण और शांति के महत्त्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

संदर्भ

[1]. Adhikari, A. (2014). The bullet and the ballot box: The story of Nepal's Maoist revolution. Verso. https://www.versobooks.com/products/18-the-bullet-and-the-ballot-box

[2]. Aitchison, C. U. (1909). A collection of treaties, engagements and sanads relating to India and neighbouring countries (Vol. 2). Government of India, Central Publication Branch.https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2182680

[3]. Barik, M., & Laishram, C. (2024). Trilateral dynamics of India–China–Nepal: Assessing geo-strategic relations in South Asia. China Report, 60(4), 430–451. https://doi.org/10.1177/00094455241289187

[4]. Bhasin, A. S. (1970). Documents on Nepal's relations with India and China . Academic Books Ltd.

[5]. Chettri, D. (2024). Reclaiming India-Nepal relation and its challenges. International Education and Research Journal, 10(11).

[6]. Chand, H. P. (2020), "Critical Issues Related to Connectivity in South Asia," Journal of International Affairs, Vol. 03, pp. 68-83, https://doi.org/10.3126/joia.v3i1.29084

[7]. Garver, J. W. (2001). Protracted contest: Sino-Indian rivalry in the twentieth century. University of Washington Press. JSTOR record

[8]. Jha, H. B. (2013). Nepal–India cooperation in river water management. Strategic Analysis, 37(2), 217–230. https://doi.org/10.1080/09700161.2012.755774

[9]. Jha, N. K. (1995). Internal security and external relations of Nepal. South Asian Publishers.

[10]. Jha, P. (2014). Battles of the new republic: A contemporary history of Nepal. Hurst & Company. https://hurstpublishers.com/book/battles-new-republic/

[11]. Johny, E. (2024). Foreign policy strategies of Nepal between China and India: Bandwagon or hedging. International Politics. https://doi.org/10.1057/s41311-024-00560-1

[12]. Kamat, R. K. (2020, May 20). Nepal to reclaim disputed territory: PM. The Himalayan Times. https://thehimalayantimes.com/kathmandu/nepal-to-reclaim-disputed-territory-pm

[13]. Kumar, A. (2021). A relook at the principle of uti possidetis in the context of the Indo-Nepal border dispute. Jindal Global Law Review, 12(1), 95–115. https://doi.org/10.1007/s41020-021-00146-5

[14]. Ministry of External Affairs. (2016). Annual report 2015–16. Government of India. https://meacms.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26525_26525_External_Affairs_English_AR_2015-16_Final_compressed.pdf

[15]. Ministry of External Affairs. (2023). Vaccine supply. Government of India. https://www.mea.gov.in/vaccine-supply.htm

[16]. Ministry of External Affairs. (2023, December 14). Details of MoUs signed with Nepal during the last three years [Parliamentary question annexure]. Government of India. https://fsi.mea.gov.in/Images/CPV/RU-1350-14-12-2023.pdf

[17]. Ministry of External Affairs. (2024). India–Nepal bilateral relations [Bilateral brief, June 20]. Government of India. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Open-bilateral-brief-20-June-2024.pdf
[18]. Ministry of External Affairs. (2025). Annual report 2024. Government of India.https://www.mea.gov.in/Images/CPV/Introduction-and-Synopsis-English.pdf
[19]. Muni, S. D. (2003). India and Nepal: A changing relationship. Konark Publishers.
[20]. Muni, S. D. (2015). India's Nepal policy. In D. M. Malone, C. R. Mohan, & S. Raghavan (Eds.), The Oxford handbook of Indian foreign policy (pp. 398–411). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198743538.013.29
[21]. Muni, S. D. (2016). India's foreign policy: The democracy norm. Cambridge University Press.
[22]. Murton, G., & A. Lord (2020). Trans-Himalayan power corridors: Infrastructural politics and China's Belt and Road Initiative in Nepal. Political Geography, 77, Article 102100. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102100
[23]. Nair, A., & Meena, T. S. (2025). Study of India–Nepal relations: An analysis of contemporary dimensions. Research Hub International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 185–190.
[24]. Nayak, N. (2010). India–Nepal Peace and Friendship Treaty (1950): Does it require revision? Strategic Analysis, 34(4), 579–593.
[25]. Pandey, N. (2020). Arun III hydropower project: A case study in Nepal-India energy cooperation. *Energy and Environment Review, 15*(2), 102-116.
[26]. Pemble, J. (1971). The invasion of Nepal: John Company at war. Clarendon Press.
[27]. Post Report. (2020, May 20). Government unveils new political map including Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura inside Nepal borders. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/national/2020/05/20/government-unveils-new-political-map-including-kalapani-lipulekh-and-limpiyadhura-inside-nepal-borders
[28]. Pun, S. B. (2011). Pancheshwar Multipurpose Project: Nepal's portion of power. *Hydro Nepal: Journal of Water, Energy and Environment*, *6*, 1–6. https://doi.org/10.3126/hn.v6i0.4186
[29]. Sharma, A. (2025A). Why does a border dispute exacerbate? Analyzing the India–Nepalese escalation over Kalapani through securitization theory. Journal of Borderlands Studies, 40(4), 881–900. https://doi.org/10.1080/08865655.2024.2394040
[30]. Sharma, J. K. (2025 B). Power, people, and pacts: A 21st century perspective on India-Nepal relations. International Journal of Social Sciences and Management, 12(2), 72–76.
[31]. Sharma, S., & P. S. Chhetri (2022). Nepal, China and 'Belt and Road Initiative': Prospects and challenges. India Quarterly, 78(3). https://doi.org/10.1177/09749284221108262
[32]. Sharma, Dinesh R. & Naresh Kazi Tamrakar (2025), "Overview on Development of Railway Line Network in Nepal, Himalaya," Asian Journal of Engineering Geology, Vol. 02 (Sp. Issue); https://doi.org/10.64862/ajeg.2025.2sp.58.175
[33]. Stiller, L. F. (1973). The rise of the House of Gorkha: A study in the unification of Nepal, 1768-1816. Manjusri Publishing House.
[34]. Thapa, C. (2025). Geopolitical implications of BRI in South Asia. Journal of APF Command and Staff College, 8(1), 191–216.
[35]. Upreti, B. R. (2010). Water resources management and India–Nepal relations. South Asian Survey, 17(2), 221–238.
[36]. Vasani, H. (2023). International water law and hydropolitics: An enquiry into the water conflict between India and Nepal. Water International, 48(2), 259–281. https://doi.org/10.1080/02508060.2023.2176595
[37]. Verma, S. (2022). The colonial legacy of India-Nepal borderland disputes. Journal of Public Affairs, 22(1), Article e2348. https://doi.org/10.1002/pa.2348
[38]. Whelpton, J. (2005). A history of Nepal. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/052180/4701/frontmatter/0521804701_frontmatter.pdf
[39]. वर्मा, स. (2023). 21वीं शताब्दी में भारत की पड़ोस नीति का अध्ययन: नेपाल के विशेष संदर्भ में. International Journal of Innovation in Engineering Research & Management, 10(1), 143–148.
[40]. सिंह, ए. (2018). दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन. इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, 6(3), 30–45.